

GOVT. OF INDIA RNI NO.: UPBIL/2015/62096

UGC Approved Care Listed Journal

ISSN
2229-3620

SIQ



शोध संचार बुलेटिन

An International
Multidisciplinary
Quarterly Bilingual
Peer Reviewed
Refereed
Research Journal

Vol. 11

Issue 41

January to March 2021

Editor in Chief

Dr. Vinay Kumar Sharma

D. Litt. – Gold Medalist



sanchar
Educational & Research Foundation



Scanned with OKEN Scanner

5.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिम तथा गैर निष्पादित परिसंपत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन	नेहा कौशिक डॉ० बायजू जॉन	137
6.	कोविड-19 महामारी में पुलिस की भूमिका	डॉ० रजनी मीना	144
7.	सामाजिक उत्तरदायित्व एवं महिला पत्रकारिता	ज्ञानी कुमारी जाट	148
8.	भारत के पाँच प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समालोचनात्मक अध्ययन	डॉ० अजीत सिंह श्रीमती मंजु अग्रवाल	152
9.	झारखण्ड की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की निम्न साक्षरता दर : समस्या और समाधान	डॉ० ओशिमा हाती संध्या सिन्हा	157
10.	मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों (बैगा, सहरिया, भारिया) की कुपोषण समस्याएँ एवं आहार अनुदान योजना का विश्लेषण	नीतू राजपूत डॉ० शैलेन्द्र सिंह तोमर	162
11.	समकालीन पुरुष लघुकथाकारों में उपस्थित स्त्री छवि का मूल्यांकन	सरिता कुमावत	167
12.	स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता	डॉ० विजय कुमार	171
13.	भारतीय संस्कृति में माँ का स्वरूप	किरीट देबनाथ	176
14.	उषा गांगुली के रंगकर्म का स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य	डॉ० अपर्णा वेणु	180
15.	आगरा शहर में नगरीकरण का सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव	रामावतार आर्य	184
16.	नगरीय विकास और उसके नकारात्मक प्रभाव (भीलवाड़ा नगर का एक विशिष्ट भौगोलिक अध्ययन)	श्रीमती सुषमा धारू डॉ० संतोष आनन्द	189
17.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जन स्वास्थ्य का प्रश्नावली के माध्यम से सांख्यिकीय विश्लेषण	डॉ० आलोक	194
18.	महात्मा गांधी की शारीरिक श्रम अवधारणा	डॉ० अभिलाषा कुमारी	200
19.	बी. एड. छात्राध्यापकों की इंटर्नशिप के दौरान आत्मविश्वास पर एक अध्ययन	श्रीमती बर्नाली राय डॉ० परविन्दर हंसपाल	204
20.	ठेकाश्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक विकास की स्थिति : एक समाजशास्त्रीय विवेचना	देवेश कुमार मेश्राम डॉ० सपना शर्मा सारस्वत	208
21.	मानवाधिकार हनन में साइबर अपराध की भूमिका	डॉ० धर्मेन्द्र तिवारी	212

झारखण्ड की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की निम्न साक्षरता दर : समस्या और समाधान

डॉ० ओशिमा हाती*
राध्या सिन्हा**

शोध सारांश

साक्षरता किसी स्थान की जनता की उन्नति और वहां की सुसंगत व्यवस्था की आधारभूत मापक होती हैं। शिक्षा और साक्षरता एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। भारत के नव-निर्मित राज्य (15 नवम्बर 2000) झारखण्ड की अनुसूचित जनजाति में साक्षरता का अभाव यहाँ के पिछड़ापन के संकेत देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियाँ देश भर में, मुख्यतया वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं। इन समुदायों की मुख्य विशेषताएँ हैं— आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच और आर्थिक रूप से पिछड़ापन। यद्यपि ऐसे मापदंड संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं हैं, लेकिन ये मापदंड लगभग सर्वमान्य और स्थापित हो चुके हैं। झारखण्ड राज्य के मूल निवासी आदिवासी ही साक्षरता की मुख्यधारा में नहीं है। ये शैक्षिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या है। किसी भी समाज या समुदाय में महिलाओं की स्थिति उस समाज या समुदाय के वास्तविक विकास की कहानी कहती हैं। इस समुदाय में महिला और बालिका साक्षरता दर की स्थिति और भी निम्न है। प्रस्तुत शोध में झारखण्ड की अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता के निम्न होने की स्थिति और कारणों का विश्लेषण किया जायेगा। कारणों कि पहचान के साथ साक्षरता बहाल करने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी।

Keywords: अनुसूचित जनजाति, महिला साक्षरता दर, साक्षरता दर की तुलनात्मक स्थिति, निम्न साक्षरता दर के कारण, उपाय।

विधि – मात्रात्मक एवं गुणात्मक, आंकड़ा विश्लेषण का आधार द्वितीयक आंकड़े होंगे।

(प्रस्तुत पत्र में आंकड़ा विश्लेषण का आधार द्वितीयक आंकड़े होंगे। इसके अध्ययन और विश्लेषण के लिए भारत, झारखण्ड, झारखण्ड के जिलों, महिला, पुरुष, ग्रामीण और नगरीय साक्षरता और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता के आंकड़े लिए गए हैं।)

सूचक— अनुसूचित जनजाति में साक्षरता लिंगभेद, ग्रामीण और नगरीय साक्षरता लिंगभेद, सामान्य और अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर की तुलना।

मुख्य स्रोत— जनगणना सूची 2011, 2011, 71वाँ एन एस एस ओ सर्वे, 2014, विद्यालय शिक्षा की सांख्यिकी 2011-12, आर्थिक सर्वे 2017-18 भारत सरकार)

सीमा – अध्ययन का आधार मुख्यतः 2011 की जनगणना सूची होगी, इसका मुख्य कारण यह है कि झारखण्ड 2000 ई० के मध्य में स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व में आया और राज्य बनने के बाद अनेक नए जिले बने। अतः जिलावार सम्यक आंकड़े 2011 में प्राप्त होते हैं।

उद्देश्य –

1. झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता का सम्पूर्ण परिचय प्राप्त करना।
2. झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता की महिला-पुरुष तुलनात्मक स्थिति और लिंगानुपात का आकलन करना।
3. झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता की ग्रामीण-नगरीय तुलनात्मक स्थिति और लिंगानुपात का आकलन करना।
4. झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य समुदाय की महिला साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति का आकलन करना।
5. झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता के साक्षरता के बाधक तत्वों का आकलन करना।

*विनागाध्यक्ष – बिजयपाल मेमोरियल बी. एड., आसनसोल

**सहायक (नेट उत्तीर्ण), शिक्षा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर